[Shri Manmohan Tudu]

Government of Orissa had requested the Ministry of Home Affairs to identify such people as S.T. But it is unfortunate that their genuine demand has been neglected.

The nature, living conditions, culture and heritage of these people are similar to those of other primitive tribes. Unless they are declared as S.T. by the Government, their status cannot be raised.

Mayurbhanj is situated on the border of West Bengal and Bihar. Therefore, the tension among the Bhanj Puran Tribe should be stopped immediately before it spreads over the border States.

As such, I request the Government of India to include the Bhanj Puran tribe as Scheduled Tribe without any further delay.

(vi) Need to set up a Central University at Bhopal on the lines of Central Schools

DR. SHANKER DAYAL SHARMA (Bhopal): National integration is the vital need of the time. Various steps are being taken in this regard. One such measure would be setting up of a Central affiliating university, following the example of Central Schools organisation which has proved of great utility to the children of Central Government employees throughout the country.

The employees of the Central Government and Public Undertakings, who are transferred from one place to another find it difficult to get admission in colleges of higher education for their children. There is the problem on account of lack of uniformity in curriculum and syllabus in institutions of higher education. Therefore, these employees prefer to remain at the same place. The proposed Central affiliating university would fill in the need for providing higher education of uniform type, syllabus and curriculum to the children of such Central Government and Public Sector employees. This will also inculcate tolerance and strengthen the bonds of unity and nationalism, which would be in the larger interest of the country. Bhopal, which is centrally located and very well connected by various means of transport, e.g. road,

rail, air etc., would be an appropriate place for the headquarters of this university. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh, the largest State in India which has no Central University. Bhopal has also been known for tolerance and freedom from State or linguistic or communal bias. This was the reason for Bhopal being chosen by Pandit Jawahar Lal Nehru as the capital of Madhya Pradesh. It would be an ideal place for locating such a university.

I would request the Government to consider this matter and prepare a scheme for setting up this university which will go a long way towards national integration.

(vii) Need for Construction of new bridges over Ganga and Yamuna, near Altahabad

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : इलाहाबाद महानगर के अन्तर्गत इलाहाबाद लखनऊ मार्ग पर गंगा
नदी पर बहुत पुराना कर्जन पुल स्थित है। पुल के
पुराने एवं कमजोर हो जाने के कारण उस पर बड़ी
एवं भारी गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगा
हुआ है। परिणामस्वरूप बड़ी बसों तथा ट्रकों को
लगभग 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय
करनी पड़ती है जिसमें प्रति-दिन समय एवं धन का
बड़ा अपव्यय हो रहा है। छोटी गाड़ियों के लिए
भी पुल पर बन—वे ट्रैंफिक रखना पड़ता है जिससे
पुल पर से गुजरना कष्टप्रद हो जाता है। अब इस
बात की नितांत आवश्यकता हो गई है कि इस
मार्ग पर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण
किया जाए। क्योंकि आवागमन दिन प्रति दिन
तेजी से बढ़ता जा रहा है।

इसी प्रकार इलाहाबाद में यमुना नदी पर भी एक पुल है। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र का औद्यो-गीकरण होने से इस पुल पर आवागमन बहुत बढ़ गया है। कभी-कभी पुल पर ट्रैफिक इस सीमा तक जाम हो जाता है कि घंटे-घंटे भर पुल पार करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस क्षेत्र में नगर के बाहर से कानपुर मार्ग को जोड़ते हुए यमुना नदी पर एक पुल अत्यावश्यक है जो बहु प्रतीक्षित है।

यदि इन पुलों के निर्माण हेतु अभी से कार्यवाही

322

प्रारम्भ नहीं की जाती तो कालांतर में इलाहाबाद महानगर के आवागमन की समस्या बहुत ही जटिल हो जाएगी। जी०टी०रोड के नगर के मध्य से गुजरने के कारण वैसे ही इलाहाबाद पर आवागमन का बड़ा दबाव है।

अतएव मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवे-दन करूंगा कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर आवश्यक-तानुसार प्रांतीय सरकार से विचार-विमर्श करके इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी पर नए पुलों के निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(viii) Need for putting up a T.V. Relay Station at Pilibhit, U.P.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): उपा-ध्यक्ष महोदय, पीलीभीत नगर व जिले में दूरदर्शन के चित्र या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते अथवा दिखाई भी देते हैं तो बिल्कुल धुंधले। पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा जिला है। दूरदर्शन का लाभ उठाने में भी यह पिछड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने टी०वी० विस्तार का जो कार्य-कम बनाया उससे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। अभी धुंधले चित्र दिखाई देने की शिकायत पर बरेली व शाहजहांपूर में दूरदर्शन केन्द्र खोले गये परन्तु उनसे भी पीलीभीत को कोई लाभ नहीं पहुंचा। वरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि केवल 25-30 किलोमीटर की है जबकि पीलीभीत बरेली से 55 किलोमीटर है, यदि बरेली के दूरदर्शन केन्द्र की परिधि 30-40 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो पीलीभीत में दूरदर्शन का लाभ पहुंच सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पीलीभीत में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करे जिससे वहां की जनता को इसके कार्यक्रमों का लाभ मिल सके अथवा बरेली के दूरदर्शन केन्द्र को इतना समकत करे कि उससे पीलीभीत लाभान्वित हो सके।

(ix) Need for providing the freedom fighters with more amenities

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष-

महोदय, देश के एक लाख सत्ताइस हजार से अधिक स्वतन्त्रता सेनानी स्वतन्त्रता-संनिक सम्मान पेंशन का उपभोग कर रहे हैं। प्रत्येक को तीन सौ रुपये और विधवाओं को दो सौ रुपये माहवारों की दर से पेंशन की राशि दी जा रही है। यह रकम आज की छलांग मारती हुई महंगाई को देखते हुए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से सरकार ने स्वतन्त्रता-सेनानियों के लिए "भारत दर्शन" के वास्ते कार्ड पास छह महीने के लिए जारी करने का निर्णय लिया था। करीब बीस हजार लोगों को ही पास मिल पाए थे कि, सरकार ने उसे बन्द कर दिया।

स्वतन्त्रता-सेनानियों की कुछ और समस्याएं भी हैं जिनकी पूर्ति की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अतः प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे इसी सत्र में स्वतन्त्रता-सेना-नियों को निम्न सुविधाएं देने की घोषणा कर उन्हें अपनी बुढ़ापे की अवस्था निश्चित होकर व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें।

- सेनानियों को मिल रही पेंशन की राशि को तीन सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये माहवारी कर दिया जाये,
- 2. सेनानियों की विधवाओं को भी पांच सौ रुपये माहवारी कर दिया जाए,
- 3. सेनानियों को सरकारी अस्पतालों से चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाये,
- 4. भारत दर्शन के लिए प्रत्येक सेनानी को रेल मंत्रालय के निर्णयानुसार छह माह के लिए ए० सी० टूटायर समेत प्रथम श्रेणी के दो रेल पास यथाशी झ दिए जाएं,
- 5. तेलंगाना, पुनप्रा, वायलार, पांडिचेरी तथा दूसरे आंदोलनों में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन की राशि दी जाए,
- 6. गांधी-इविन समझौते के बाद जेल से छुटने वाले सभी सेनानियों को पेंशन की सुविधा दी जाए।